नेताओं पर निगरानी

संवैधानिक आदर्शों के अनुसार भले ही जन-प्रतिनिधि लोकसेवक होते हैं, पर यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि सांसद, विधायक या मंत्री बनकर कई नेता अपनी संपत्ति बढ़ाने का भी जुगाड़ करते हैं. चुनाव के मौकों पर अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि कई सांसदों और विधायकों की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हो गयी. ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार से इस संबंध में निगरानी का कोई इंतजाम नहीं होने के बारे में सवाल पूछना जायज ही है. पिछले साल फरवरी में देश की सबसे बड़ी अदालत ने टिप्पणी की थी कि जनता द्वारा निर्वाचित विधायिका के सदस्यों द्वारा बेतहाशा संपत्ति जमा करना लोकतंत्र के असफल होने का सूचक है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो हमारा लोकतंत्र तबाह हो जायेगा और माफिया शासन के लिए रास्ता खुल जायेगा. इसके साथ उसने निर्वाचित नेताओं की कमाई पर निगरानी के लिए ठोस व्यवस्था करने का निर्देश दिया था. सालभर बीतने के बाद भी इस दिशा में सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गयी है. इसी कारण अदालत को अब सफाई मांगनी पड़ी है. चुनाव में नामांकन के समय संपत्ति का आधा-अधूरा ब्योरा देना भी परिपाटी-सी बन गयी है. इस मसले पर भी सरकारी रवैये के बारे में जवाब-तलब किया गया है. चुनाव समेत विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में धन और बल का इस्तेमाल तथा इस अवैध खर्च की भरपाई के लिए विधायिका और कार्यपालिका में मिले पद का दुरुपयोग ऐसी चुनौतियां हैं कि इनसे छुटकारा पाये बिना स्वस्थ लोकतंत्र की अपेक्षा नहीं की जा सकती है. पिछले साल के फैसले में अदालत ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की थी कि इतने अहम मसले पर भी संसद और चुनाव आयोग का कोई ध्यान नहीं है. हमारे देश की बड़ी आबादी गरीबी में और कम आमदनी में गुजारा करती है. सामाजिक और आर्थिक विषमता को पाटने तथा सर्वांगीण विकास की आशा को पूरा करने के लिए प्रयास करने एवं नेतृत्व देने का उत्तरदायित्व विधायिका और कार्यपालिका को है. यदि इनके स्तर पर ही राजनीतिक भ्रष्टाचार की अनदेखी होगी, तो फिर और उपाय क्या रह जायेगा ! संवैधानिक संस्था होने के बावजूद चुनाव आयोग के पास समुचित अधिकार नहीं हैं. आयोग को शक्तिशाली बनाने और चुनाव सुधार के कानून बनाने के विधि आयोग के अनेक सुझाव लंबे समय से सरकार के पास लंबित हैं. मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग ठीक से कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि उसके पास प्रत्याशियों के बारे में सभी प्रासंगिक सूचनाएं हों. समुचित पारदर्शिता के बिना भ्रष्ट और अपराधी चुने जा सकते हैं, बल्कि चुने जाते रहे हैं. एक समस्या यह भी है कि किसी तथ्य को छुपाने या जन-प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करने का कोई मामला सामने आता है, तो आयोग, विधायिका और न्यायालयों को उसके निपटारे में बहुत समय लग जाता है. इस पर भी सोचा जाना चाहिए. उम्मीद है कि अदालती निर्देशों का पालन तत्परता से करने की कोशिश होगी.

सांसदों और विधायकों की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी को लेकर सरकार से निगरानी का कोई इंतजाम नहीं होने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल पूछा है.

अब भी द्वंद्व में है कांग्रेस

नवीन जोशी
वरिष्ठ पत्रकार
naveengjoshi@gmail.com

इसी मंगलवार को अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यसमिति ने लोकसभा चुनाव के लिए जो रणनीति तय की, उसका मुख्य ध्येय है- 'आरएसएस-भाजपा की फासीवादी, नफरत व गुस्से से भरी और विभेदकारी विचारधारा को परास्त करना.' उद्देश्य बड़ा, बेहद चुनौतीपूर्ण और कांग्रेस की मूल नीतियों को समाहित करनेवाला है. सवाल है कि यह उद्देश्य कैसे पूरा होगा? इसके लिए कांग्रेस ने कौन सा रास्ता या तरीका चुना है? क्या इस बारे में भी वह स्पष्ट है?

सत्रहवीं लोकसभा के लिए मतदान कार्यक्रम के ऐलान के तुरंत बाद जिस समय कांग्रेस की सर्वोच्च समिति यह तय करने बैठी, उस वक्त सत्तारूढ़ भाजपा और संघ बेहतर तैयारी और दमखम के साथ मैदान में डटी दिखायी देती है. पांच साल सत्ता में रहने के बावजूद वह बचाव की मुद्रा में नहीं है, बल्कि विपक्ष के प्रति बहुत आक्रामक है. उसे ललकारने की स्थिति में तो कांग्रेस को होना चाहिए था, लेकिन वह स्वयं भारी द्वंद्व में पड़ी लगती है.

हाल के कुछ उदाहरण कांग्रेसी असमंजस का संकेत देते हैं. वह साफ-साफ यह तय नहीं कर पा रही कि उसे इस चुनाव में भाजपा को किसी भी तरह सत्ता में आने से रोकने की कोशिश पर ध्यान देना चाहिए या उससे सीधे भिड़कर अपना छीजा राजनीतिक आधार वापस पाने की दूरगामी राजनीति पर फोकस करना चाहिए.

कांग्रेस आज जहां है, वहां उसे 2014 की तुलना में कुछ पाना ही है. अभी कोई इस संभावना पर सहमत नहीं होगा कि कांग्रेस का यह हासिल इतना बड़ा हो सकता है कि वह अकेले भाजपा से सत्ता छीन ले. कांग्रेस नेतृत्व को ऐसा लगता, तो वह किसी द्वंद्व में पड़ने की बजाय भाजपा को सीधी चुनौती देता. लंबे समय से किसी महागठबंधन या क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग की बात ही क्यों उठती?

क्या कांग्रेस के पास ऐसा कोई जमीनी आकलन है कि वह लोकसभा में 44 सीटों की अपनी संख्या में कितनी वृद्धि कर सकेगी? वह भाजपा को किस आंकड़े पर रोक पाने की स्थिति में है? और, क्या उसने 2019 की भाजपा की ताकत और कमजोरियों का अध्ययन-विश्लेषण किया है? क्या यही अस्पष्टता उसके द्वंद्व का प्रमुख कारण नहीं है?

उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लें. इस आम चुनाव में उसे भाजपा को किसी भी तरह सत्ता में पुनः आने से रोकने की रणनीति पर चलना है, तो सपा-बसपा-रालोद के मजबूत गठजोड़ में शामिल होने का फैसला काफी पहले कर लेना था. अब तो मायावती ने कांग्रेस से कहीं भी गठबंधन करने से साफ मना कर दिया है, वरना कांग्रेस का एक मन आज भी इस गठबंधन के साथ है. दूसरा मन उसे यहां अपनी पहचान और भी खो देने का डर दिखा रहा है. इसलिए वह लगभग सभी सीटों पर लड़ने की घोषणा कर रही है, जबकि ज्यादातर सीटों पर पार्टी संगठन के पांव ही उखड़े हुए हैं. अकेले लड़ कर भविष्य की राह खोलनी थी, तो संगठन को खड़ा करने में समय रहते ध्यान क्यों नहीं दिया?

कांग्रेस अब लड़ाई में वापस आने का रास्ता ढूंढ रही है. कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की क्षमता की परख इस बात से होगी कि वह भाजपा के राष्ट्रवाद के चुनावी-कवच को कितना जल्दी भेद पाता है.

दिल्ली की सात सीटों पर 'आप' से गठबंधन के बारे में भी उसका यही द्वंद्व सामने आया है, जबकि 'आप' भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस से तालमेल को आतुर थी. बंगाल और केरल में माकपा से उसकी बात ही चलती जा रही है. कर्नाटक में सहयोगी जनता दल (सेकुलर) से खट-पट है. आंध्र में तेलुगु देशम से रिश्ता टूट चुका है. महाराष्ट्र में एनसीपी से तालमेल अब भी विवाद में है. क्षेत्रीय दलों से सहयोग की रणनीति का यह हाल है. गुजरात में कांग्रेस से अपने विधायक ही नहीं संभल रहे. आखिर किस बूते वह भाजपा को परास्त करने की सोच रही है?

क्या तीन राज्यों में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास अति-विश्वास में बदल गया? राहुल गांधी मोदी सरकार पर बहुत आक्रामक हो रहे थे. राफेल विमान सौदे से लेकर किसान असंतोष, बेरोजगारी, नोटबंदी की अब तक जारी मार, मॉब लिंचिंग, संवैधानिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि की स्वायत्तता पर हमले, अल्पसंख्यकों में भय का वातावरण जैसे कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरनेवाले सवाल उठा रहे थे. तभी पुलवामा में आतंकी हमले में चालीस जवानों की शहादत और बालाकोट के आतंकी ठिकाने पर वायुसेना के जवाबी हमले ने परिदृश्य उलट दिया.

अब भाजपा मजबूत नेता, देश की सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मुद्दे लेकर आक्रामक हो उठी है. कांग्रेस के तरकश के तीर भोथरे पड़ गये हैं. मौके पकड़ने और उन्हें शस्त्र की तरह राजनीतिक शत्रुओं पर इस्तेमाल करने में दक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर लोकप्रियता की लहर पर सवार हैं. उनके विरुद्ध जो भी नकारात्मक था, वह फिलहाल नेपथ्य में चला गया.

अब कांग्रेस लड़ाई में वापस आने का रास्ता ढूंढ रही है. उसके नेतृत्व का कौशल यह होना चाहिए कि वह भाजपा को उसकी विफलताओं तथा जनता के ज्वलंत मुद्दों से घेरकर वापस उस खुले मैदान में खींच लाये, जहां वह बालाकोट हमले से पहले खड़ी थी. उसके शीर्ष नेतृत्व की क्षमता की परख इस बात से होगी कि वह भाजपा के राष्ट्रवाद के चुनावी-कवच को कितना जल्दी भेद पाता है.

उधर भाजपा के पास आज ऐसा 'शक्तिशाली, अजेय और विकल्पहीन' लगनेवाला नेता है, जैसा कभी इंदिरा गांधी के रूप में कांग्रेस के पास था. भाजपा सरकार की कई विफलताओं के बावजूद नरेंद्र मोदी की छवि सफल और सशक्त नेता की बनी हुई है. 'मोदी है तो मुमकिन है' नारे पर पूरा फोकस करके भाजपा उनकी इसी छवि के साथ चुनाव मैदान में डटी हुई है.

राहुल गांधी भी कांग्रेस के एकछत्र नेता हैं, लेकिन पार्टी और जनमानस पर उनकी पकड़ की कोई तुलना मोदी से करना कठिन है. कुछ ज्वलंत मुद्दों पर वे मोदी को सीधी चुनौती देते हैं, लेकिन पुलवामा-आतंकी हमले के बाद मोदी के राष्ट्रवाद का मुकाबला करने का कोई प्रभावी तरीका राहुल तलाश नहीं पा रहे. मोदी इस मुद्दे पर बहुत आक्रामक रूप से जुटे हैं कि 'देश सुरक्षित हाथों में है.'

कांग्रेस से कहीं बेहतर स्थिति में होने के बावजूद सहयोगी दलों के प्रति भाजपा ने नरम रवैया अपनाया. उसने लगभग सभी नाराज सहयोगी दलों को मना लिया है. एनडीए को कायम रखने के लिए उसने समझौते करने में संकोच नहीं किया. उधर, कांग्रेस लंबे समय से गठबंधन और क्षेत्रीय तालमेल की बात करने के बावजूद अब तक किसी ठिकाने पर नहीं पहुंच पायी है.

'गठबंधन करे या एकला चले' का कांग्रेस का द्वंद्व जारी है. यह रवैया अहमदाबाद में तय रणनीति के अनुरूप नहीं है. अभी मुद्रा बचाव की है और समय बहुत कम.

खंडित ही होगा तमिल जनादेश

आर राजागोपालन
वरिष्ठ पत्रकार
rajagopalan1951@gmail.com

जे जयललिता एवं एम करुणानिधि जैसे कद्दावर नेताओं के निधन के पश्चात तमिलनाडु तो जैसे अब एक नेता विहीन राज्य बन गया है. अगली लोकसभा के लिए आगामी 18 अप्रैल, 2019 को तमिलनाडु में संपन्न होनेवाले आम चुनावों के अभियान में इन दोनों नेताओं की कमी शिद्दत से महसूस की जायेगी. पहले तो डीएमके ने यह घोषणा की कि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी उसके पसंदीदा उम्मीदवार होंगे. उसके बाद एडीएमके ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया.

एडीएमके ने भाजपा के साथ ही विजयकांत के 'डीएमडीके' एवं डॉ रामादोस के 'पीएमके' के साथ अपने शक्तिशाली गठबंधन को अंतिम रूप देकर डीएमके के सामने कड़ी चुनौती पेश कर दी है. उसी तरह डीएमके ने भी कांग्रेस तथा कुछ अन्य छोटी राज्यस्तरीय पार्टियों के साथ अपना गठबंधन कर स्वयं को मजबूत करने की कोशिश की है. डीएमके ने तमिलनाडु में मोदी विरोधी अभियान का नेतृत्व कर ऐसी हवा बनाने की कोशिश की थी कि वह तमिलनाडु तथा पुडुचेरी की सभी 40 सीटें जीत लेगा. पर जयललिता के नक्शे-कदम पर चलते हुए एडापडी पलानीस्वामी ने बगैर किसी शोर-शराबे के भाजपा के साथ होशियारी से गठजोड़ कर तमिलनाडु विधानसभा में अपने अल्प बहुमत के बावजूद सत्तारूढ़ बने रहने में कामयाबी हासिल कर ली.

दरअसल, तमिलनाडु की सियासत समझने के पहले उत्तर भारतीय पाठकों को इस राज्य में विभिन्न जातियों का आपसी समीकरण समझने की जरूरत है. थेवर, नडार, गोंडर तथा वन्निआर- ये चार जातियां मिलकर तमिलनाडु में सरकारें बनाने या बिगाड़ने की हैसियत रखती हैं. जयललिता तथा करुणानिधि ने इस समीकरण को संभाले रखा, पर एमके स्टालिन इसमें उतने सफल साबित न हो सके. मगर उन्होंने अल्पसंख्यकों को अपने पाले में जरूर कर रखा है. वहीं दूसरी ओर, एडीएमके अपने 33 प्रतिशत वोटबैंक को सुरक्षित रखने में सफल रहा है. ये ऐसे मतदाता हैं, जो एमजी रामचंद्रन एवं जयललिता के घोर समर्थक रहे हैं. लेकिन, करुणानिधि के बाद डीएमके के पास कोई उनके जैसा करिश्माई नेता नहीं रह गया है.

इस तरह, इस राज्य की राजनीति में एक शून्य सरीखा उत्पन्न हो गया है. क्या नरेंद्र मोदी इस शून्य की भरपाई कर इसका लाभ उठा सकेंगे अथवा इस कार्य में राहुल गांधी बाजी मार ले जायेंगे? पिछले तीन महीनों के दौरान नरेंद्र मोदी इस राज्य का चार बार दौरा कर चुके हैं. इस मोर्चे पर राहुल गांधी भी कोई पीछे नहीं हैं. भाजपा को एडीएमके के हिंदुत्व एजेंडे का लाभ मिलेगा. यहां यह स्मरणीय है कि दक्षिण में एडीएमके वह पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, जिसने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया था. जयललिता ने पार्टी के लगभग सभी घोषणापत्रों में इसे शामिल कराया. तमिलनाडु सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य है, जहां डीएमके के अनीश्वरवादी प्रभाव के बावजूद त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में जाते रहे हैं. डीएमके ने आरक्षण को 80 प्रतिशत तक बढ़ा कर अगड़ी जाति विरोधी भावनाएं भुनाने की कोशिश की है.

आगामी चुनाव बड़े नेताओं के बाद पहली बार तमिलनाडु के द्वितीय पंक्ति के नेताओं को यह मौका देने जा रहा है कि वे इसमें अपनी नेतृत्व क्षमता को प्रमाणित करें. ऐसे में सवाल है कि पलानीस्वामी क्या जयललिता का स्थान ले सकेंगे? उधर डीएमके की आंतरिक सियासत के नजरिये से स्टालिन के लिए तो यह करो या मरो की स्थिति है. करुणानिधि के निधन के बाद स्टालिन के भ्राता एमके अलागिरी ने पार्टी छोड़ दी. अभी इस पार्टी को करुणानिधि परिवार के छह सदस्य मिलकर संचालित कर रहे हैं. एडीएमके खुद भी विभाजित है, क्योंकि टीटीवी दिनाकरण ने उसे चुनौती दे रखी है.

तमिलनाडु की फिजा में अभी जयललिता एवं एमजी रामचंद्रन के सुरीले फिल्मी नगमे गूंज रहे हैं. उधर डीएमके ने करुणानिधि के दमदार भाषणों तथा उनके तमिल क्षेत्रीयतावादी प्रचार का सहारा ले रखा है. एडीएमके नमो प्रभाव का फायदा उठाने के अलावा कांग्रेस तथा राहुल गांधी को श्रीलंका में दो लाख तमिलों के नरसंहार की विरासत का दोषी ठहरा रहा है. वहां श्रीलंका अब भी चुनावी मुद्दा बना हुआ है. मोदी के विरोध में डीएमके राफेल सौदे एवं तथाकथित मोदी कुशासन की बातें उठाते हुए किसानों और कामगार वर्ग के मुद्दों को हवा दे रहा है.

इतना तो तय है कि तमिलनाडु तथा पुडुचेरी के कुल 40 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमा पाना दोनों में से किसी भी पार्टियों के लिए संभव नहीं हो सकेगा. करुणानिधि या स्टालिन के पक्ष में कोई लहर नहीं है, तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ एडीएमके पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं. अंततः जनादेश खंडित ही रहेगा. अनुमानों के अनुसार, सत्तारूढ़ दल के गठबंधन को 15 से 18 लोकसभा सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि डीएमके भी 15 से 20 सीटें पा सकता है. इस तरह, दोनों दलों के लिए यह नतीजा लगभग 50-50 के अनुपात का होगा. वहीं, दिनाकरण द्वारा भी दो सीटें हथिया लिये जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है. केंद्र में ऊंट चाहे जिस करवट भी क्यों न बैठे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कम से कम पांच सदस्य तमिलनाडु से जरूर शामिल रहेंगे.

(अनुवाद : विजय नंदन)

आगामी चुनाव बड़े नेताओं के बाद पहली बार तमिलनाडु के द्वितीय पंक्ति के नेताओं को यह मौका देने जा रहा है कि वे इसमें अपनी नेतृत्व क्षमता को प्रमाणित करें. पलानीस्वामी क्या जयललिता का स्थान ले सकेंगे?

बोधि वृक्ष

इतिहास बनाओ

हमारे देश के बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि जो व्यक्ति, जीवन में शीर्ष स्थान पाना चाहता है, उसे अपना मार्ग स्वयं बनाना पड़ता है. शायद इसलिए कहा गया है कि महापुरुष अपने कदमों के निशां स्वयं बनाते हैं. इसलिए हर शख्स को अपना मार्ग स्वयं बनाना पड़ता है. नदी जब हिमालय से चलती है, तो वह स्वयं अपना मार्ग बनाती चलती है. इसलिए मनुष्य को अपना कर्म और दायित्व स्वयं निर्धारित करना चाहिए और उसी पर चलना चाहिए. यही जीने की कला है. हमें जीवन का संरक्षण और विकास खुद ही करना होगा. हमारे देश में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने किसी दूसरे का अनुकरण नहीं किया, अपितु अपना मार्ग स्वयं बनाया. इसलिए मैं बच्चों को परामर्श देता हूं कि- बड़ों का अनुकरण नहीं, उनका नेतृत्व करो. अनुकरण करनेवाला व्यक्ति कभी इतिहास पुरुष नहीं बनता. आज इस देश को ऐसे बच्चों की आवश्यकता है, जो अपने कार्यों, विचारों और संस्कारों से समाज का नेतृत्व कर सकें. ऐसे व्यक्ति समाज में तभी पैदा होंगे, जब शुरू से हम अपने बच्चों को जीवन से प्यार करना सिखायें. जीवन से हताश, निराश और दुखी व्यक्ति कभी कोई सफलता प्राप्त नहीं करता. हमेशा प्रसन्न रहनेवाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है. जो लोग हिमालय के शिखर पर चढ़ते हैं, समुद्र की गहराई मापते हैं, चांद-तारों की यात्रा करते हैं, वे लोग भी मनुष्य ही हैं. लेकिन, वे अपने जीवन से प्रेम करते हैं. तभी वे इतने बड़े-बड़े काम पूरा करते हैं. आज समाज में वैसे ही लोगों की आवश्यकता है, जो इतिहास बना सकें. जो वीर पुरुष होते हैं, वही अपने कदमों के निशां बनाते हैं और जो व्यक्ति असंभव काम को भी पूरा कर लेता है, वही व्यक्ति राष्ट्रपुरुष बनता है. लेकिन, ऐसा वही कर सकता है, जिसको अपने जीवन से मोह हो, इसलिए हमें अपने जीवन से प्रेम करना सीखना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल माना जायेगा. हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि- भविष्य के द्वार पर तुम्हें ही दस्तक देना है, अपने कदमों की आहट से इतिहास नया बनाना है.

आचार्य सुदर्शन

आपके पत्र

सैनिक कार्रवाई पर राजनीति

धर्म, सेना और राष्ट्रवाद, इन्हीं तीन विषयों पर आज देश की राजनीति हो रही है. कोई भी दल या नेता बालाकोट हवाई हमले का सबूत मांगता है, तो उसे राष्ट्र विरोधी कहा जाता है. बिहार के एक कांग्रेसी नेता ने पार्टी से इस्तीफा दिया क्योंकि उनकी पार्टी के द्वारा सैनिक कार्रवाई का सबूत मांगना उन्हें अच्छा नहीं लगा. क्या किसी देश की सेना को अपने द्वारा की गयी कार्रवाई का सबूत देना पड़ता है? नहीं. दुनिया के विकसित देश जैसे अमेरिका और इजरायल द्वारा की गयी सैन्य कार्रवाई में ऐसा नहीं होता. अपने देश की राजनीति धर्म और जाति के अलावा सैनिक कार्रवाई पर भी चल रही है. सेना को किसी देश की राजनीति मुद्दा बनाना बहुत ही शर्मनाक है. पाकिस्तान में सेना की अहम भूमिका होती है राजनीति में, परंतु हम पाकिस्तान से अलग हैं. और हमें अलग ही रहने की जरूरत है. इसलिए सेना को राजनीति से दूर रखना जरूरी है.

अभिषेक मोहन, रांची

शराब पर पूर्ण प्रतिबंध जरूरी

शराब से हो रही निरंतर मौतों के अतिरिक्त इससे इंसान, परिवार, समाज और राष्ट्र बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि यह अनेक बीमारियों, धन की बर्बादी और ढेर सारे जुर्मों की जननी है. शराब में जो डूबे, उभरे न कभी जिंदगानी में, लाखों बह गये इन बोतलों के बंद पानी में. जिस घर में घर का मुखिया या परिवार का कोई सदस्य शराबी हो, तो उस घर की महिलाओं की स्थिति खराब हो ही जाती है और वे सदा नरक ही भोगती है. दुख की बात है कि शराब के कारण महिला उत्पीड़न और हत्याएं तक आम हो गयी हैं. दुर्भाग्य से सरकार इस पर राज्य को होनेवाली आय का कुतर्क देती है, जो सरासर गलत है. बिहार एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहा है. ऐसे अनेक गलत और अवैध कार्यों से होनेवाली आय क्या कभी उचित हो सकती है? इसलिए इस पर पूर्ण प्रतिबंध बहुत जरूरी है. इसकी जगह अच्छे खाद्य और पेय पदार्थों का भी उत्पादन करना ही सर्व हित में है.

वेद मामूरपुर, नरेला

सही प्रत्याशी का चयन करें

देश का दुर्भाग्य है कि यहां के पढ़े-लिखे युवा भी किसी गंभीर और वास्तविक मुद्दे पर संगठित नहीं होते, लेकिन कथित देशभक्ति के लिए सिर पर साफा बांध कर, तिरंगा झंडा लेकर झुंड में निकल पड़ते हैं. मोटर साइकिलों पर शहर में रैली के लिए मिनटों में हजारों युवा जुट जाते हैं. अधिकतर मीडिया चैनल बेमतलब विषयों पर दिन-रात बहस कराते रहते हैं. इनको देश की वास्तविक समस्याओं मसलन बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, किसानों की आत्महत्या, भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि समस्याओं के लिए समय नहीं है. अब समय आ गया है जब हम बेहतर प्रत्याशी का चयन कर सकते हैं जो भविष्य में इन सारे विषयों पर गंभीरता से काम करे. इसलिए हम सभी को अपनी बुद्धि व विवेक का प्रयोग करना है. जाति, धर्म आदि पर राजनीति करने वाले लोगों से सावधान रहकर, अगले चुनाव में शिक्षित, ईमानदार, कर्मठ उम्मीदवारों का चुनाव करें.

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

कुछ अलग

आध्यात्मिक फिजाओं की खुशबू

कविता विकास
रचनाकार
kavitavikas28@gmail.com

भारत में हर ऋतु के अनुसार खान-पान, पर्व-उत्सव और कर्मकांड होते हैं. माघ मेला, पौष मेला, कुंभ मेला, दशहरा मेला आदि एक स्थान विशेष में होते हुए भी विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति को समेटे होते हैं. मेला जब गंगा के किनारे हो तब उसका महत्व और भी बढ़ जाता है. गंगोत्री से निकली गंगा कूदती-फांदती उत्तर प्रदेश-बिहार पहुंचते-पहुंचते युवा हो जाती है. थोड़ी चपलता, थोड़ा गांभीर्य. और बात जब संगम के गंगा की हो तो क्या कहने ! संगम की गरिमा और इसकी महिमा से हर व्यक्ति परिचित है.

संगम किनारे से गुजरते हुए लगता था कि पलकें भी ना झपकें, नहीं तो कुछ छूट ना जाये. देशी-विदेशी पर्यटकों के स्वागत में कोई कमी नहीं थी. सड़कें सुगठित. वैसे तो कुंभ मेले में पहले भी जाना हुआ है, पर इस बार जैसा विहंगम दृश्य कभी नहीं देखने को मिला था. मेले भारतीय सनातन परंपरा के मुख्य अंग रहे हैं, जो धर्म और परंपराओं के संवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं. कुंभ मेले में तो मानो आध्यात्मिक फिजाओं की खुशबू अपनी ओर खींच रही हो. जगह-जगह संत पंडालों के मंत्रोच्चार और ऋषियों के सद्-वचन एवं तत्वमीमांसा के उद्गार अपनी समृद्ध संस्कृति को उजागर कर रहे थे.

पूरे वातावरण में धर्म, मंत्र और आस्था का मिला-जुला प्रभाव था. अलग-अलग खेमे में अलग-अलग अखाड़ों का अड्डा था. चेहरे विशिष्ट रंगों से रंगे हुए. मुझे वहीं पता चला कि हरेक अखाड़े के सदस्यों में तिलक लगाने और चेहरे के रंग-रोगन के प्रकार भिन्न-भिन्न होते हैं. एक की शैली दूसरे से अलग होती है, जो उनकी विशिष्ट पहचान है. कल्पवासियों के अलग खेमे थे. कभी मुग्धकारी संगीत गूंजता, तो कभी नादों का समवेत अनहद नाद.

संगम में डुबकी लगाने के साथ देवताओं के नाम अर्घ्य अर्पण करके सचमुच लगा कि जन्म-जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलने का रास्ता खुल गया. यह पुण्य स्नान अतीत के कुकर्मों का मूल्यांकन कर भविष्य में सुकर्मों की ओर प्रेरित करता है. यह मेला सनातन संस्थाओं और आम जनमानस के बीच सीधा संबंध जोड़ता है. कहते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम को ओंकार नाम से अभिहित किया गया है. ओंकार का 'ओम्' परब्रह्म परमेश्वर की ओर रहस्यात्मक संकेत करता है. अमृत कलश को निकालने में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा का विशेष योगदान था. मन, आत्मा और ज्ञान के सम्मेलन से ही आध्यात्मिक शक्ति का उद्भव होता है, जो कुंभ स्नान के बाद पापों का नाश कर मोक्ष का मार्ग बनाती है.

जिस यात्रा पर जाने के लिए आप मन से उत्साहित हों, जिसका आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व हो तथा जिसकी महिमा में अटूट आस्था हो, तो वह यात्रा सर्वोत्तम होती है. कुंभ मेले के दौरान तथा पश्चात मुझे कभी न तो थकावट हुई और न कभी शोरगुल से परेशानी. करोड़ों लोगों के साथ चलना द्योतक है कि अपनी मिट्टी की विरासत में भारतीय मूल्य और नैतिकता की गहरी पैठ है.

देश दुनिया से

भारत पर दबाव डालने का अमेरिकी पैंतरा

इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अमेरिका में व्यापार करने के लिए दिये गये विशेषाधिकार, जो भारत से निर्यात की जानेवाली 5.6 बिलियन डॉलर मूल्य के वस्तुओं को बिना शुल्क अमेरिका में प्रवेश की अनुमति देते हैं, को समाप्त करने के संकेत दिये थे. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह कदम भारत सरकार के उन नये कानूनों, जिनका उद्देश्य भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र को बराबरी पर लाना है, को लक्षित करने के लिए उठाया गया है. भारत के इन नये कानूनों से अमेजन और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट जैसे अमेरिकी दिग्गजों को नुकसान पहुंच सकता है. भारत को वैश्विक भुगतान दिग्गज मास्टरकार्ड और वीजा द्वारा अपने भुगतान डेटा को भारत में संग्रहित करने और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे स्मार्टफोन पर आयात शुल्क बढ़ाने की जरूरत थी. जब अमेरिका ने इस पर चिंता जतायी थी, तो भारत ने इसके मद्देनजर उपाय करने शुरू कर दिये थे. भारत के व्यापार विशेषाधिकार को समाप्त करने का ट्रंप का नवीनतम निर्णय भारत को उसके नियमों को बदलने और अमेरिकी दिग्गजों के लिए उसके ई-कॉमर्स और खुदरा बाजार खोलने के लिए मजबूर करना है.

GLOBAL TIMES

लौंग शिंगचुन व झाओ रुओक्सी

कार्टून कोना

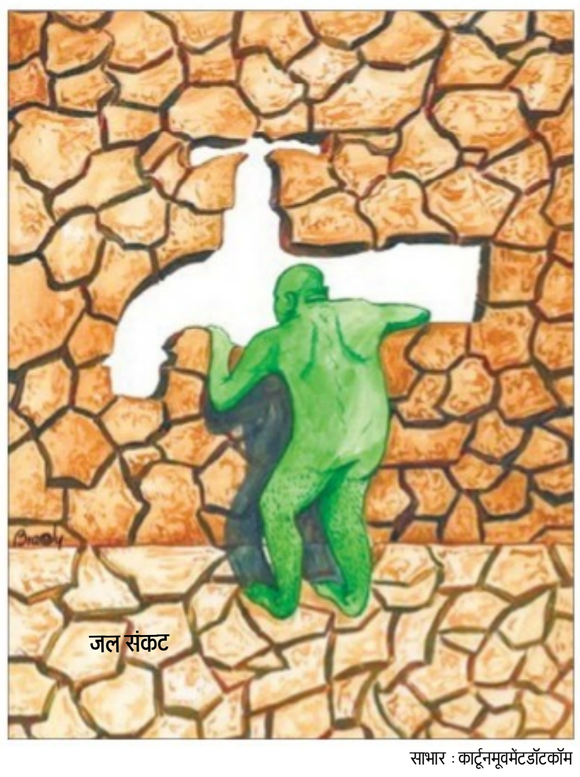

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है